

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओपीओबिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 211/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1- इलमदीन पुत्र मिश्रीखां 2- मोहम्मद खां पुत्र मिश्रीखां 3- आमदीनपुत्र मिश्रीखां 4- युसुफखां पुत्र मिश्रीखां 5- रमजान पुत्र मिश्रीखां 6- रफीक पुत्र सतारखां 7- निसारखां पुत्र सतार खां 8- इनायत उल्ला पुत्र सतार खां 9- सलीम पुत्र सतार खां 10-सिकन्दर पुत्र सतार खां 11-जीन्नत पत्नी सतार खां जातियान सिंधी मुसलमान निवासीगण ग्राम सडी ढाणी, तहसील बाप जिला जोधपुर		1- अब्दुल अजीज पुत्र कमरे खां 2- गफूर खां पुत्र कमरे खां 3- इस्माईल खां पुत्र कमरे खां जातियान सिंधी मुसलमान, निवासीगण ग्राम बडी ढाणी, तहसील बाप जिला जोधपुर 4- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध आदेश दिनांक 9-3-2021 जो उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2020 में पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री पूनाराम बिश्नोई अधिवक्ता अपीलार्थियों की ओर से ।
- 2- श्री मनोहर सिंह राठौड अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 1 से 3 की ओर से
- 3- श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30-5-2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पोंड संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम बडी ढाणी के खसरा नंबर 2187 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 2187/2938 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2192 रकबा 137 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 161 बीघा 06 बिस्वा स्थित है । उक्त खसरा नंबरान की पैमाईश दिनांक 6-1-2020 को की गई जिस पर अप्रार्थीगण असंतुष्ट है इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी की जायें । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में वर्तमान अपीलांतगण को बतौर अप्रार्थीगण बनाया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विधिवत नोटिस तामिल करवाये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 18-8-2020 को अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर तहसीलदार बाप से जवाब प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंड संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन आदेश दिनांक 9-3-2021 को पारित कर दिया जाने से अपीलार्थीगण को अपीलार्थीगण के विरुद्ध



राजस्थान सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी पडौसी खातेदारो को अवसर देकर उनकी मौजुदगी मे धारा 111 के तहत निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट आने के बाद ही किसी खसरे की भूमि के पत्थरगढी का आदेश पारित करने चाहिये थे परंतु इस प्रकरण मे वर्तमान अपीलार्थीगण को कोई नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा कार्यवाही कर फर्द पैमाईश दिनांक 6-1-20 अनुसार पुलिस इमदाद के साथ पत्थरगढी करने बाबत आदेश दिनांक 9-3-2021 को पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण खसरा नंबर 2169, 2170, 2171 के रेकर्डेड खातेदार है तथा जिन खसरो का पत्थरगढी करने का आदेश जारी किया है, उनके पडौसी खातेदार है इस कारण अपीलांटगण प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा उनकी गैर मौजुदगी मे तैयार फर्द पैमाईश दिनांक 6-1-2020 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए केवल तहसीलदार का जवाब प्राप्त कर बिना प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण मौके पर पीढियो से काबिज है तथा रेस्प0 उक्त पत्थरगढी आदेश की आड मे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये हमे बेदखल करना चाहते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 608 तथा आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 918 जिसमे धारा 111, 128 एल. आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र मे प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकारो को नोटिस दिया जाना आवश्यक बताया है इसलिए उक्त निर्णय नजीरो के परिपेक्ष्य मे अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

'रेस्प0 संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि प्रत्येक खातेदार को अपने खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं पत्थरगढी कराने का पूर्ण अधिकार है इसी के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया तथा उक्त प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारान (वर्तमान अपीलांटगण) को पक्षकार बनाया गया था । वकील रेस्प0 संख्या 1 से 3 ने कथन किया कि अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये थे जिनकी रसीदे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है फिर भी वे अधीनस्थ न्यायालय मे जानबझकर पकरण को लंबा करने की मंशा

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांत की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो० संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 6-1-2020 के संबंध में कथन किया कि उक्त सीमांकन फर्द पंडौसी खातेदारान की उपस्थिति में तैयार की गई थी जिस पर पंडौसी खातेदारान ने असंतुष्टि जाहिर करने का उल्लेख है । इसलिए अपीलांत अधिवक्ता का यह कथन सही नहीं है कि सीमांकन फर्द मौका अपीलांतगण की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई थी ।

अंत में वकील रेस्पो० संख्या 1 से 3 ने अपील की उक्त अपील सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि कराने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्तमान अपीलांत को पक्षकार बनाकर उन्हें नोटिस रजिस्टर्ड भेजे गये तथा यह भी कथन किया कि सीमांकन फर्द अपीलांतगण की उपस्थिति में तैयार की थी परंतु उन्होंने उसे इंकार कर दिया इसलिए यह नहीं माना जायेगा कि अपीलाधीन आदेश उनको नोटिस दिये बिना पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि आदि का भी अध्ययन किया । वर्तमान अपील में अपीलांत अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि उनके नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में व्यक्तिगत तामिल नहीं हुए थे तथा अधीनस्थ न्यायालय में केवल रजिस्टर्ड नोटिसेज भिजवाने की रसीदों के आधार पर तामिल मानकर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह प्रकट है कि अप्रार्थीगण के नोटिसेज रजिस्टर्ड जारी करने बाबत कोई आदेश नहीं होते हुए अप्रार्थीगण के नोटिसेज रजिस्टर्ड प्रेषित किये गये तथा जिनकी रजिस्ट्री रसीद दिनांक 7-3-20 की अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है तथा प्राप्ति रसीद/ए.डी. सभी पर केवल रफीक लिखा हुआ है उसकी कोई सकूनत आदि का उल्लेख नहीं है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त रफीक नामक व्यक्ति कौन है, जिसको तामिल मानते हुए आदेशिका दिनांक 18-8-2020 में अप्रार्थीगण संख्या 2 से 12 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं, जो विधिसम्मत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हम हस्तक्षेप करना न्यायोचित समझते हैं ।

परिणामस्वरूप हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 0-2-2021 में आंगिक संशोधन करने का प्रस्ताव आंगिक



वति • सम्भागीय बायुक्त
बोधपुर

राजस्व अपील संख्या 211/2021 इलमदीन वगैरा बनाम अब्दुल अजीज वगैरा

जारी कर नोटिस तामिल होने के पश्चात विधिवत सीमाज्ञान/पत्थरगढी का आदेश पारित करें । तत्पश्चात सीमाज्ञान/पत्थरगढी की कार्यवाही दोनो पक्षकारान की उपस्थिति मे भू अभिलेख निरीक्षक की अध्यक्षता मे टीम गठित कर की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 30-5-2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।



(ओ०पी०बिश्नोई)
अतिरिक्त सहाय्य आयुक्त
जोधपुर